



पीएम मोदी ने किया चिन्मय अमृत महोत्सव का उद्घाटन, कहा-
चिन्मय मिशन सिर्फ एक संस्था नहीं, ये चिन्मय विचार हैं

नई दिल्ली २३/१०
(संवाददाता): नई दिल्ली में चिन्मय अमृत महोत्सव ग्लोबल सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत उन्नति को राष्ट्रीय प्रगति का माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद की शिक्षाओं का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे इस आध्यात्मिक गुरु ने आध्यात्मिक विकास को राष्ट्र के विकास से जोड़ने का प्रयास किया। भारत मंडप में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक वैदिक मंत्र, वयं राष्ट्र जागृत्याम पुरोहिताः का उल्लेख किया। यह मंत्र नागरिकों का आह्वान करता है कि वे राष्ट्र को जागरूक और उन्नत बनाने की दिशा में काम करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का भला चाहने वाले लोगों के रूप में, हमारा कर्तव्य है कि हम



राष्ट्र को जागरूक और उन्नत बनाएं। स्वामी चिन्मयानंद जी ने अपना पूरा जीवन इसी मंत्र से प्रेरित होकर जिया प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को लोगों के अस्तित्व का आधार बताया और स्वामी चिन्मयानंद के उस विचार को याद किया, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति को व्यक्तिगत उन्नति और राष्ट्रीय विकास से जोड़ने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में अपने देश के प्रति आत्म-सम्मान की भावना जगाना स्वामी जी का मिशन

था। इसी उद्देश्य से उन्होंने—
%गीता ज्ञान यज्ञ% की शुरुआत
की और उपनिषदों, वेदों तथा
हमारे धर्मग्रंथों के ज्ञान को आम
लोगों तक पहुँचाया। आज हम
उनके उस संकल्प का परिणाम
देख सकते हैं।

चिन्मय मिशन के बारे
में बात करते हुए, प्रधानमंत्री
मोदी ने इसे केवल एक संस्था
से कहीं बढ़कर बताया। उन्होंने
इसे एक आध्यात्मिक संत की
दूरदृष्टि से उजाज चिन्मय विचार
कहा। उन्होंने कहा कि आप
सभी की शुभकामनाओं से,

आज मुझे चिन्मय मिशन के
अमृत महोत्सव का हिस्सा बनने
का अवसर मिला है।

यह एक बिल्कुल अलग तरह का आध्यात्मिक अनुभव है। यह मेरे प्रति हमारे संतों का विशेष स्नेह और आशीर्वाद है। उन्होंने आगे कहा कि चूँकि चिन्मय मिशन केवल एक संस्था नहीं है, बल्कि यह एक 'चिन्मय विचार' है, जिसकी नींव एक 'चिन्मय ऋषि' ने रखी थी।

दशकों की इसकी यात्रा भी 'चिन्मय संकल्पों' से भरी रही है। और जो कुछ भी 'चिन्मय' है, वह स्वाभाविक रूप से अमर है, वह अमृतमय

है। उन्होंने कहा कि 2047 में भारत जब अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, उसी कालखंड में चिन्मय मिशन भी अपनी शताब्दी का वर्ष मनाएगा। यानी चिन्मय मिशन की शताब्दी यात्रा और विकसित भारत की यात्रा एक साथ आगे बढ़ेगी।

इसलिए हमारे लक्ष्य भी एक हैं, उद्देश्य भी एक है और हमें इस यात्रा को एकसाथ आगे बढ़ाना है।

मोदी ने कहा कि बीते दशकों में समय बदला है, देश के सामने नई चुनौतियाँ पैदा हुई हैं, समाज में नई विकृतियाँ आई हैं। आज उनके समाधान का दायित्व हम सबके ऊपर है। आज हमें बांटने वाली ताकतों के खिलाफ समाज को एकजुट करना है। हमें आत्मनिर्भरता के लिए देशवासियों को जागरूक करना है। 2047 में विकसित भारत के सफल से जन-जन को डेना है।

इन उद्देश्यों के लिए हमें
और सक्रिय होना है। चिन्मय
मिशन के प्रयास से आज लाखों
युवा हैं... जो भारत के
सांस्कृतिक ब्रांड एंबेसडर का
काम कर रहे हैं। ये भारतीय
युवा पत्रिका को नई पीढ़ी तक
पहुँचा रहे हैं।

ओम प्रकाश माथुर बने केरलम के २९वें राज्यपाल, लोक भवन में ली पद की शपथ



और मुख्य न्यायाधीश समेत कई लोग शामिल हुए। लगभग सभी मंत्री और हमारे विधायक वहां मौजूद थे।

जोसेफ ने ANIको बहुत गर्व की बात है। राजस्थान में भाजपा के वरिष्ठ नेता और संघ के प्रचारक ओम प्रकाश माथुर ने कई पदों पर काम किया है, जिनमें भाजपा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष और संगठनात्मक सचिव के रूप में उनकी भूमिकाएं शामिल हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में कई

हमें इस समारोह में शामिल होकर खुशी हुई है। राजस्थान के मंत्री संजय शर्मा ने माथुर की नियुक्ति को राजस्थान के लिए गर्व का क्षण

जिम्मेदारियां निभाई हैं, दो बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं और कई राज्यों में पार्टी के प्रभारी के तौर पर चुनाव प्रबंधन का काम भी संभाला है।

दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरे वाम दल

नयी दिल्ली २३/१० (संवाददाता): नई दिल्ली में बांग्ला साहिब गुरुद्वारे के पास कई वागमर्थी दलों और छात्र नेताओं ने एक मार्च निकाला-उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की और मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण का विरोध किया। मध्य दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ निकाले गए एक मार्च के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। ये प्रदर्शनकारी मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाए जाने के विरोध में भारतीय चुनाव आयोग के मुख्यालय की ओर जा रहे थे। CPI के राष्ट्रीय महासचिव डी. राजा ने कहा कि आज एक आह्वान किया गया है। देखते हैं कि लोग कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और यह किस तरह एक कड़ा संदेश पहुंचाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर नहीं बने रह सकेंगे। उन्हें इस्तीफा देना होगा। पीपल



अगस्ट SIR विरोध प्रदर्शन के दौरान CPI नेता एनी राजा ने कहा कि हम देश को केंद्र के उन कपटपूर्ण तरीकों से बचाने के लिए यहाँ आए हैं, जिनका मकसद लोकतंत्र को नष्ट करना है। सीपीआई नेता पी. संतोष ने कहा कि हमारा विरोध और तेज होगा; ज्ञानेश कुमार को कोई नहीं बचा सकता। CPI(M) नेता वृंदा करात ने कहा कि जब तक श्रद्धा ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बांग्ला साहिब गुरुद्वारे से जंतर-मंतर की ओर लोगों की भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की और दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच रूट डायवर्जन की घोषणा की। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने आधिकारिक %३% (टिवटर) अकाउंट के जरिए लोगों को सलाह दी कि वे प्रभावित रास्तों से बचें, अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें। यह मार्च, स्ट्रोक प्रक्रिया को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन और %कॉकरोच जनता पार्टी के चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच निकाला गया। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण (रिवीजन) में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है।

कांग्रेस ने लोकतंत्र दिया तभी पीएम मोदी आज शीर्ष पद पर हैं-शिव कुमार

बेगलुरु २३/१०
(संवाददाता): कर्नाटक के
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने
शुक्रवार को कहा कि भारत में
लोकतंत्र स्थापित करने में कांग्रेस
ने अहम भूमिका निभाई है।
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी आज जिस पद पर
हैं, वह देश की लोकतांत्रिक
व्यवस्था में कांग्रेस के योगदान
की ही देन है।

शिवकुमार की यह टिप्पणी मोदी के उस आरोप के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को अपना प्रमुख राष्ट्रीय नेता बनाने के लिए सालों तक लगातार कोशिशें कीं। शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि कांग्रेस के बिना यह देश लोकतंत्र नहीं देख



पाता। यह वह पार्टी है जिसने लोकतंत्र दिया है। अगर आज वे (मोदी) प्रधानमंत्री हैं, तो यह भारत के नेतृत्व और लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी के योगदान की वजह से ही है। उन्होंने कहा कि किसी को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। अगर आप जड़ें भूल जाएंगे, तो आपको फल नहीं मिलेगा। गुरुवार को मोदी ने विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया एक

नई व्यवस्था की तलाश कर रही हैं, तब कुछ लोग भारत में अव्यवस्था का सपना देख रहे हैं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सीधे हमला करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने नेता को लॉन्च करने की इतनी बार असफल कोशिशें की हैं, जितनी बार भारत ने एक साल में श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च नहीं किए होंगे।

अयोध्या २३/१०
(संवाददाता): उज्जर प्रदेश के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
शुक्रवार को कहा कि अयोध्या
में आयोजित होने वाला 10वां
दीपोत्सव भारतीय संस्कृति,
सनातन परंपरा और जनआस्था
का भव्य उत्सव होगा। योगी
ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र
मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2017
में शुरू हुई दीपोत्सव की यात्रा
अब वैश्विक पहचान हासिल कर
चुकी है।

उन्होंने निर्देश दिया कि दीपोत्सव के एक दशक पूरे होने के अवसर पर इस वर्ष भी राम की पैड़ी सहित संपूर्ण अवधपुरीराम को पिछले साल की तरह लाखों दीपों से रोशन किया जाए। यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सात नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री

ने निर्देश दिए कि आयोजन की धार्मिक गरिमा, सांस्कृतिक परंपरा और भव्यता के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

उन्होंने श्रद्धालुओं और अतिथियों की सुविधा, सुरक्षा, सुगम आवागमन, प्रकाश, स्वच्छता और मार्गदर्शन की समुचित व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री को तैयारियों की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव (पर्यटन एवं संस्कृति) ने बताया कि

दीपोत्सव का आयोजन तीन प्रमुख चरणों में होगा। पहले चरण में साकेत महाविद्यालय से भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसमें रामायण के प्रसंगों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन आदर्शों को दर्शाया जाएगा। दूसरे चरण में रामकथा पार्क में भगवान श्रीराम और माता सीता के स्वरूपों का प्रतीकात्मक आगमन, भरत मिलाप और श्रीराम के राज्याभिषेक से जुड़े कार्यक्रम

होंगे। तीसरे चरण में सरयू, आरती, दीप प्रज्वलन, राम की पैड़ी पर 200 कलाकारों की प्रस्तुतियां, 2,100 ड्रों के माध्यम से रामायण पर आधारित आकाशीय प्रदर्शन, लेजर शो, गोंडा पुल के समीप हरित आतिशबाजी और अंतरराष्ट्रीय रामलीलाओं का मंचन होगा।

इस उत्सव में करीब 35 हजार स्वयंसेवक भाग लेंगे।
आयोजन के प्रमुख आकर्षणों में 2,147 प्रतिभागियों द्वारा सरयू आरती, 2,100 स्वदेशी डोनों के माध्यम से आकाशीय प्रस्तुति, त्रिआयामी (3डी) प्रोजेक्शन और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल

होंगे। डिजिटल माध्यमों से दीपोत्सव को पांच करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

गया कि उज्जर प्रदेश के अलावा मध्यप्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, बिहार, केरल, गोवा और तेलंगाना के करीब एक हजार कलाकार लोककलाओं और नृत्य परंपराओं की प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा, 12 देशों के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों की भागीदारी प्रस्तावित है। भारत में तैनात विदेशी राजदूतों और विदेशों में तैनात भारतीय राजनयिकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। बैठक में विचारक स्थित रामघाट के चित्रकूट और श्रद्धालुओं की सुविधाएं बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई।

मुज्यमन्त्री ने कहा कि हाल में अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का प्राथमिकता के आधार पर पुनर्विकास कराया जाए।



विविध समाचार



दिल्ली रेसकोर्स मस्जिद को लेकर जबरदस्त घमासान, वक्फ बोर्ड पर उठते सवालों के बीच सियासी बयानबाजी के चलते मामला गर्माया

नयी दिल्ली २३/१० (संवाददाता): दिल्ली की रेस कोर्स मस्जिद को लेकर विवाद गरमा गया है। मुस्लिम नेता इसे धार्मिक अधिकारों पर हमला बता रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सरकारी जमीन पर कच्चे का है। हम आपको बता दें कि मस्जिद के प्रतिनिधि 1977 के दिल्ली गजट में वज़फ संपज्ञि के रूप में दर्ज होने और विरासत स्थल की मान्यता का हवाला दे रहे हैं, जबकि सरकारी विभाग जमीन पर कच्चे को अनधिकृत बता रहा है। ऐसे में सवाल है कि ज़्या वज़फ में दर्ज होने या ऐतिहासिक इमारत होने भर से सरकारी जमीन पर कच्चे का अधिकार मिल जाता है? अगर मस्जिद के पास वैध दस्तावेज हैं, तो उन्हें अदालत में पेश कर कानूनी लड़ाई ज्यों नहीं लड़ी गई? इस विवाद में सरकार की कार्रवाई के साथ-साथ वज़फ बोर्ड की भूमिका और राजनीतिक नेताओं की

बयानबाजी भी सवालों के घेरे में है। हम आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने मस्जिद के प्रतिनिधियों को परिसर खाली करने के लिए छह दिन का नोटिस जारी किया। विभाग का पक्ष है कि जमीन सरकारी है और वहां मौजूद ढांचा अनधिकृत है। दूसरी ओर, मस्जिद के प्रतिनिधि 1977 के दिल्ली गजट में वज़फ संपज्ञि के रूप में दर्ज होने और एनडीएमसी की विरासत सूची में शामिल होने का हवाला दे रहे हैं। लेकिन इस मामले में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास भी सामने आया है। 15 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद का बिजली और पानी का कनेक्शन बहाल करने से इंकार कर दिया था। ये कनेक्शन 7 अक्टूबर को काटे गए थे। वहीं, 22 अक्टूबर को सरकारी सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया कि मस्जिद को कोई बेदखली

नोटिस नहीं भेजा गया। ऐसे में सवाल है कि आखिर वास्तविक स्थिति ज़्या है? ज़्या नोटिस जारी किया गया था, किसे दिया गया था और सरकार की अलग-अलग स्तरों पर सामने आ रही जानकारी में अंतर ज्यों है? देखा जाये तो मस्जिद के समर्थन में सबसे प्रमुख दलील उसका वज़फ संपज्ञि के रूप में दर्ज होना और ऐतिहासिक महत्व है। लेकिन किसी संपज्ञि का वज़फ रिकॉर्ड में दर्ज होना और संबंधित जमीन पर वैध मालिकाना हक या कच्चे का अधिकार होना दो अलग-अलग कानूनी प्रश्न हैं। यदि मस्जिद के पास जमीन के मालिकाना हक, वैध आवंटन, लीज या किसी अन्य कानूनी संरक्षण से जुड़े दस्तावेज हैं, तो उन्हें संबंधित प्राधिकरण और अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए। केवल दशकों पुराने धार्मिक ढांचे का हवाला देकर जमीन



के स्वामित्व का विवाद अपने आप खत्म नहीं हो जाता। इसी तरह, सरकारी विभाग के नोटिस को भी अंतिम न्यायिक फैसला नहीं माना जा सकता। असली कसौटी जमीन के रिकॉर्ड और लागू कानून होंगे। साथ ही विरासत का दर्जा भी अपने आप मालिकाना हक नहीं देता। यह दर्जा किसी इमारत के संरक्षण और उसमें बदलाव या तोड़फोड़ की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इससे जमीन पर अनधिकृत कच्चा स्वतः वैध नहीं हो जाता। सवाल यह है कि ज़्या मस्जिद के प्रतिनिधियों ने अपने दावों को कानूनी रूप

से स्थापित करने के लिए प्रभावी न्यायिक कार्रवाई की? देखा जाये तो इस विवाद का सबसे गंभीर पहलू दिल्ली वज़फ बोर्ड की भूमिका है। मस्जिद के इमाम मौलाना मोहज़्मद हारून के मुताबिक, उन्होंने महीनों तक बोर्ड से मदद मांगी, लेकिन न तो प्रभावी कानूनी कार्रवाई हुई और न ही उन्हें अदालत जाने की अनुमति दी गई। इस बीच, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सोशल मीडिया पर बोर्ड द्वारा आदेश को चुनौती नहीं दिए जाने और 2023 से उसके पूर्ण रूप से गठित नहीं होने का मुद्दा उठाया।

यदि ये आरोप सही हैं, तो सवाल केवल सरकार से नहीं, उस संस्था से भी होना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी वज़फ संपज्ञियों के हितों की रक्षा करना है। सवाल उठता है कि बोर्ड ने समय रहते कानूनी रास्ता ज्यों नहीं अपनाया? जमीन से जुड़े दस्तावेज सामने ज्यों नहीं रखे गए? साथ ही विवाद बढ़ने के बाद जवाबदेही तय करने की मांग इतनी कमजोर ज्यों दिखाई दी? उधर, यह मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। जमीनगत उलेमा-ए-हिंद के प्रतिनिधिमंडल ने भी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रिज्जू से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने मस्जिद का दौरा करने की घोषणा की है। वहीं कश्मीर के मीरवाइज उमर फारूक ने इसे मुस्लिम धार्मिक

स्थलों की सुरक्षा से जोड़ते हुए वज़फ संशोधनों और सरकारी नियंत्रण पर सवाल उठाए हैं। जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुज्ती नासिर-उल-इस्लाम ने भी इस घटनाक्रम पर चिंता जताई है। लेकिन ज़्या बयान जारी करना, मंत्रियों से हस्तक्षेप की मांग करना और समुदाय की भावनाओं का हवाला देना जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण बन सकता है? यदि मस्जिद के पक्ष में ठोस कानूनी दस्तावेज हैं, तो उन्हें अदालत में निर्णायक रूप से सामने लाने की जरूरत है। और यदि वज़फ बोर्ड ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, तो उसकी जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। हम आपको यह भी बता दें कि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, रेस कोर्स रोड के पास लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट में दो मंदिरों, एक अनधिकृत मस्जिद और हिंदू-मुस्लिम दोनों

समुदायों के आवासों पर कार्रवाई का उल्लेख है। एक स्थानीय महिला के अनुसार, प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से ज़लैट मिले हैं और वे इससे संतुष्ट हैं। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास से सटा हुआ है। बहरहाल, मामला किसी ढांचे के धार्मिक नाम का नहीं, बल्कि सरकारी जमीन पर वैध अधिकार और कानून के पालन का है। यदि जमीन पर कच्चा अनधिकृत है, तो केवल धार्मिक पहचान, ऐतिहासिक महत्व या राजनीतिक दबाव के आधार पर कार्रवाई को अनिश्चितकाल तक नहीं रोका जा सकता। सरकारी जमीन की सुरक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और नियमों का उल्लंघन साबित होने पर नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई होनी ही चाहिए। आखिर सरकारी संपज्ञि पर अवैध कच्चे को कब तक बर्दाश्त किया जाए?

वोट चोरी एक साबित हकीकत, जयराम रमेश बोले-झूठ के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा इकोसिस्टम

नयी दिल्ली २३/१० (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को उन पर झूठ फैलाकर लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का इकोसिस्टम हताशा और घबराहट में है। कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता ने केंद्र सरकार पर मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया और कहा कि वोट चोरी एक साबित हो चुकी सच्चाई है। एड्स पर एक पोस्ट में जयराम ने लिखा वोट चोरी एक साबित हो चुकी सच्चाई है। श्वेदु (चुनाव आयोग) के अपने आंकड़ों के अनुसार, 10 करोड़ से अधिक भारतीयों के सामने अपना संबैधानिक वोटिंग अधिकार खोने का खतरा है। श्वेदु ने नए मतदाताओं के लिए रुकावटें पैदा करने के लिए फॉर्म 6 में गैर-कानूनी तरीके से



बदलाव किए हैं। इसने चुनिंदा लोगों के नाम हटाने के लिए %फॉर्म 7% के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को बढ़ावा दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त (श्वेदु) पर निशाना साधते हुए, उन्होंने कहा कि श्वेदु ने सभी कानूनी सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के नागरिकों में भारी गुस्सा है और सज़ाधारी दल के दमन के बावजूद देशभर में विरोध-प्रदर्शन चल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, CEC ने सभी कानूनी सुरक्षा उपायों को दरकिनार करते हुए, मतदाता सूची पर अपना नियंत्रण

केंद्रित करने के लिए श्वेदुहथ्थु का इस्तेमाल किया है। देश में भारी आक्रोश है। लोगों में बहुत गुस्सा है और दमन के बावजूद विरोध-प्रदर्शन जारी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी पूरी तरह से बेनकाब हो गई है और जनता उनसे जवाब मांगेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का इकोसिस्टम, अपनी हताशा और घबराहट में, अब लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। वे वही कर रहे हैं जो उनके छद्म में है झूठ फैलाना। लेकिन

वे सफल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और जनता उनसे जवाब मांगेगी। इस बीच, विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी नकारात्मक राजनीति के कारण 2030 तक भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे केवल घुसपैठियों के वोट बैंक को बचाने के लिए वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही, उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी कि पंजाब से उनकी पार्टी का सफाया हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में एक सभा को संबोधित करते हुए, गृह मंत्री ने भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर कांग्रेस पार्टी द्वारा बार-बार उठाए जा रहे सवालों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह पुरानी पार्टी हारने

पर हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं को ही दोष देती है। शाह ने कहा मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ कि आप %वोट चोरी% के आरोप लगाकर घुसपैठियों के वोटों को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस कई राज्यों में दशकों से चुनाव नहीं जीत पाई है, और यह सिलसिला प्रधानमंत्री मोदी के सज़ा में आने से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। कांग्रेस की चुनावी स्थिति पर तंज कसते हुए शाह ने आगे कहा आप जिस तरह की नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि आप 2030 तक भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे... जहां आप जीतते हैं, वहां चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन जब भी आप हारते हैं, तो चुनाव आयोग में ही खोट नजर आने लगता है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो याद रखें कि अगले 30 सालों तक आपकी बारी नहीं आने वाली है।

नयी दिल्ली २३/१० (संवाददाता): कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत की चीन नीति पर स्पष्टता देने की मांग की है। उन्होंने सीमा सुरक्षा, आर्थिक संबंधों और राजनयिक मामलों को संभालने के सरकार के तरीके की आलोचना की है। %ङ्ग% (टिवटर) पर एक पोस्ट में, खड़गे ने प्रधानमंत्री से तीन खास सवाल पूछे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक निर्भरता और राजनयिक जवाबदेही से जुड़े हैं। उन्होंने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक के उस बयान का जिक्र किया, जिससे पुष्टि होती है कि अरुणाचल प्रदेश में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ आमना-सामना चल रहा है। खरगे ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में के साथ लगातार हो रहे टकराव की दृष्टिक्रम के छल द्वारा पुष्टि, बेहद चिंताजनक है। डोकलाम और गलवान के बाद, ज़्या एक और गंभीर टकराव की स्थिति बन रही है? अगस्त में तज़िंग के पास चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आई थीं। फिर भी, वाचा-दमाई में कोर कमांडर स्तर की बातचीत के 47 दिन बाद भी - जो कि कथित तौर पर यहाँ से केवल 180 किमी दूर है - टकराव जारी है। ज़्या भारत की पेट्रोलिंग (गश्त) की पहुँच प्रभावित हुई है?



अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। देश को अंधेरे में ज्यों रखा जा रहा है? उन्होंने 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद से चीन के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गलवान में भारतीय सेना के 20 बहादुर जवानों की शहादत (स्रङ्घु2020-21) के बाद से, चीन से आयात में 102ब की भारी वृद्धि हुई है, जबकि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 155ब बढ़कर 112.16 अरब डॉलर हो गया है। यहाँ तक कि विज़ मंत्री निर्मला सीतारमण भी मानती हैं कि चीन भारतीय निर्यात में बाधा डालता है। इसके बावजूद, सरकार चीनी निवेश पर लगी पाबंदियों में ढील दे रही है और चीन से जुड़ी पात्र कंपनियों को %प्रोडक्शन-लिंज़ड ईसेंटिव देने पर विचार कर रही है। ज़्या %मेक इन इंडिया%अब %ईंपोर्ट फॉर्म चाइना% (चीन से आयात) बन गया है? राजनयिक प्रयासों के संबंध में,

खड़गे ने कहा कि मोदी और शी के बीच कम से कम 23 मुलाकातें और बातचीत हुई, ह्द अजीत डोभाल के साथ विशेष प्रतिनिधियों के 25 दौर की वार्ताएं हुईं, %परामर्श और समन्वय के लिए एक कां तंत्र% की 36 बैठकें हुईं, और इसके अलावा स्टह तथा ऋङ्गहृष्ट के लगातार शिखर सम्मेलन हुए। इन मुलाकातों और वार्ताओं का ज़्या ठोस नतीजा निकला? ज़्या मई 2020 से पहले भारत को हासिल गश्त (पेट्रोलिंग) करने के अधिकार पूरी तरह से बहाल हो गए हैं? उन्होंने सशस्त्र बलों पर भरोसा जताते हुए सरकार की राजनयिक कार्यशैली की आलोचना की-हमें अपने सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जवाबदेही जरूरी है, न कि राजनयिक फोटो-अवसर या गले मिलने वाली कूटनीति (हगप्लोमेसी) !विपक्ष पर हमला करने के बजाय, प्रधानमंत्री मोदी को संसद और पूरे देश को विश्वास में लेना चाहिए।

अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली उच्च न्यायालय से झटका, शांति बॉण्ड नोटिस में दखल से इनकार

नयी दिल्ली २३/१० (संवाददाता): दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पुलिस के उस नोटिस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें ‘ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन’ (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा से शांति बनाए रखने के लिए बॉण्ड भरने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के पास बोरा के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने बोरा की 17 अक्टूबर के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि नोटिस कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप था और यह केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित नहीं था। अदालत ने कहा कि इस चरण में उच्च न्यायालय एसईएम की जगह बैठकर

सामग्री के प्रति उनकी व्यक्तिपरक संतुष्टि की जांच नहीं कर सकता। संबंधित सामग्री में छात्र नेता का उल्लेख करने वाली छह प्राथमिकी, विभिन्न स्थानों पर हुई कुछ घटनाओं से संबंधित सामान्य डायरी की प्रविष्टियां और मंडी हाउस इलाके में निषेधाज्ञा लागू होने की जानकारी शामिल थी। अदालत ने कहा, जिस इलाके में याचिकाकर्ता को हिरासत में लिया गया था और जहां वह लोगों से अपने विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने की अपील कर रही थीं, वहां शांति भंग होने की आशंका को लेकर एसईएम का यह मानना था कि वह एक व्यावसायिक इलाका है, जहां दत्तचर जाने वालों की भारी आवाजाही रहती है। साथ ही, वहां से कुछ महत्वपूर्ण सड़कें गुजरती हैं, जो शहर के मुख्य हिस्से को अन्य इलाकों से जोड़ती हैं। उसने कहा, वहां बड़ी



संज़्या में होटल, बैंक, कार्यालय और विक्रेता हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 और 130 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने से पहले एसईएम के पास कोई सामग्री नहीं थी। अदालत ने कहा, इतना कहना पर्याप्त है कि इस अदालत की राय में बीएनएसएस की धारा 126 के तहत कार्रवाई किए जाने से पहले मजिस्ट्रेट के पास पर्याप्त

सामग्री थी। बीएनएसएस की धारा 126 एसईएम को ऐसी स्थिति में बॉण्ड भरवाने का अधिकार देती है, जब विश्वसनीय सूचना हो कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, सार्वजनिक शांति भंग कर सकता है या ऐसा गलत कार्य कर सकता है, जिससे अशांति फैलने की आशंका हो। अदालत ने 46 पन्नों के फैसले में अस्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता उचित चरण पर (जिसमें एसईएम की ओर से अंतिम आदेश दिए जाने के बाद का समय भी शामिल है) नयी चुनौती पेश करने के लिए स्वतंत्र है। उसने पुलिस को निर्देश दिया कि वह जांच के समय याचिकाकर्ता को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए। अदालत ने एसईएम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि बॉण्ड भरने का आदेश देने से पहले प्राकृतिक

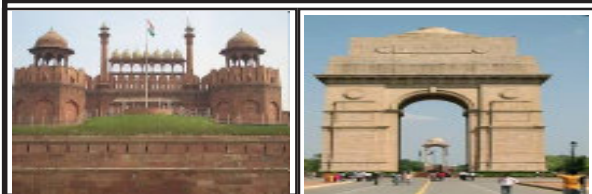
न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन न हो। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शनों में अग्रणी भूमिका निभा रही बोरा ने नोटिस रद्द करने और पुलिस को उनके खिलाफ बलपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। बोरा को 24 अक्टूबर को दोपहर दो बजे एसईएम के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान बोरा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने दलील दी थी कि नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है और लोकतंत्र में सज़ा परिवर्तन की मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है।

सौरव दास और आशुतोष रांका कोर्ट में हुए पेश, अगली सुनवाई 17 नवंबर को

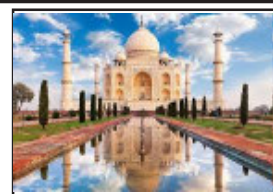
नयी दिल्ली २३/१० (संवाददाता): शुक्रवार दोपहर को कोकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन स्थित स्पेशल एंजीन्यूटिव मजिस्ट्रेट (स्वर्क) कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने उन्हें जमानतदारों के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने अपनी ज़मानत सत्यापन रिपोर्ट में बताया है कि दास ने दिल्ली में अपने वर्तमान आवासीय पते की पुष्टि या सत्यापन के लिए कोई दस्तावेज़ नहीं दिया है।

इसलिए, अदालत ने उनसे कहा है कि वे सुनवाई की अगली तारीख, यानी 17 नवंबर को, अपने पते की पुष्टि के लिए कोई दस्तावेज़ पेश करें। कार्रवाई में शामिल होने से पहले, दास मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए कुछ देर पुलिस स्टेशन के बाहर रुके। उन्होंने कहा कि आगे ज़्या कदम उठाना है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पुलिस स्टेशन में ज़्या होता है। जब उनसे पूछा गया कि ज़्या वे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो दास ने कहा, देखते हैं, यहाँ ज़्या होता है। उनके साथ श्वक्क की लीगल

अफेयर्स हेड रत्ना सिंह भी थीं। दास और रंका अपने खिलाफ दर्ज दो मामलों की जांच में शामिल होने के लिए पुलिस के समन पर पेश नहीं हुए, और इस मामले में उन्हें एक और नोटिस जारी किया जाना था। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दास, रंका और श्वक्कसदस्य अर्जिज़्य शिंदे को गुरुवार को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था। एक अधिकारी ने कहा कि पहले उन्होंने और समय मांगा था, लेकिन बाद में वे नहीं आए।



विविध समाचार



आईटी सर्च में नाम आने पर रकुल प्रीत सिंह ने दी सफाई

अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने इनकम टैक्स छापां से अपना नाम जुड़ने की खबरों पर रिएक्ट किया। अभिनेत्री ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। दरअसल, 28 सितंबर को आयरकर विभाग ने अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और फिल्म निर्माता वासु भगनानी से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। 28 सितंबर 2026 को मुंबई में आयरकर विभाग ने इंस्टाग्राम पर एक नोट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मीडिया द्वारा गलत अफवाहों को फैलाने पर अफसोस जताया। उन्होंने लिखा, 'यह देखकर बहुत दुख होता है कि आजकल कुछ खुद को रिपोर्टर कहने वाले लोग और कुछ बड़े मीडिया पत्रकार बिना सच्चाई जाने खबरों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहे हैं। इसलिए, मैं एक बार फिर सब कुछ साफ कर देती हूँ।' उन्होंने आगे लिखा, 'अभी हाल ही में हमारे घर में जो तलाशी हुई है, उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। इस बात हर कोई वाकफ है कि मैं एक फौजी परिवार से ताल्लुक रखती हूँ और इंडस्ट्री में मेरा कोई गोंडफादर नहीं था। मैं अपनी कड़ी मेहनत से यहां तक पहुंची हूँ और 20 साल की उम्र से एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना पूरा टैक्स भी भरती आ रही हूँ।' अभिनेत्री ने साफ किया कि उनका नाम किसी भी गैरकानूनी कामों से जुड़ा नहीं है। उन्होंने लिखा, 'मैं किसी भी तरह के गैरकानूनी विदेशी लेनदेन में शामिल नहीं हूँ, न तो खुद के लिए और न ही किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए। मैं यह भी साफ कर दूँ कि मेरे नाम पर देश या विदेश में कहीं भी गैरकानूनी प्रॉपर्टी नहीं है। न ही कभी किसी ने मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट की और न ही मैं इस तरह से तोहफे स्वीकार करती हूँ।' अभिनेत्री ने अफवाह फैलाने वाले मीडिया संस्थानों से अपील कि की वे इस तरह की खबरें न फैलाएं। उन्होंने लिखा, 'जिनोंने मेरे खिलाफ मनगढ़ंत खबरें छपी हैं। मैं उनसे उस खबर को वापस लेने की अपील करती हूँ, साथ ही सच्चाई बताने के लिए कहती हूँ। मैं समझती हूँ कि मीडिया पर भी अपना बिजनेस चलाने का दबाव होता है लेकिन यह दबाव सच्चाई की कीमत पर नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी किसी की इज्जत और रोजी-रोटी की कीमत पर तो नहीं होना चाहिए।'



टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में धूम मचाएगी जिमी शेरगिल और दिव्या दत्ता की फिल्म

जिमी शेरगिल और दिव्या दत्ता अपनी फिल्म 'तुम रहे ना तुम' को लेकर वर्चस्व में आ गए हैं। साइकोलॉजिकल फेमिली ड्रामा का 10 अक्टूबर को टोरंटो में 'इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साउथ एशिया' (आईएफएफएसए) में वर्ल्ड प्रीमियर होगा। यह फिल्म 'गाला प्रीमियर' के तौर पर दिखाई जाएगी। यह फिल्म स्वीडिश नाटककार ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग के महाहूर नाटक 'द फादर' पर आधारित है। इसमें नाटक के साइकोलॉजिकल और इमोशनल पहलुओं को आज के भारतीय परिवार के माहौल में नए सिरे से दिखाया गया है। उत्तराखंड के एक पहाड़ी शहर पर आधारित यह फिल्म एक पति-पत्नी की कहानी है, जिनकी बेटी के भविष्य को लेकर शुरू हुई लड़ाई

आगे चलकर एक गंभीर संघर्ष में बदल जाती है। 'तुम रहे ना तुम' मुख्य रूप से पावर, विरासत, माता-पिता की उम्मीदों और बच्चे का भविष्य तय करने के अधिकार जैसे मुद्दों को दिखाती है। साथ ही, यह भी दिखाती है कि पितृसत्ता, असुरक्षा और भावनात्मक घाव कैसे किसी परिवार को बदल सकते हैं। फिल्म की स्टारकास्ट इस फिल्म के निर्देशक प्रेम मोदी है। इसमें जिमी शेरगिल और दिव्या दत्ता मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसमें तनिष्का तिवारी, हर्ष छया, जरीना वहाब और राजेश जैस कलाकार अहम किरदारों में हैं। इसी ध्वनी चावला, वृंदा चावला और सोनू कात्याल ने 'फेनेटिकली फिल्मी प्राइवेट लिमिटेड' के बैनर तले प्रोड्यूस किया है।

कमल हासन की फिल्म इंडियन 3 का पोस्ट-प्रोडक्शन काम शुरू

कमल हासन और निर्देशक एस. शंकर की फिल्म 'इंडियन 3' को लेकर लंबे समय से असमंजस की स्थिति थी। दरअसल, 'इंडियन 2' के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करने के बाद माना जा रहा था कि शायद यह फिल्म बंद हो गई है। लेकिन अब फिल्म दोबारा पटरी पर आ गई है और इसका पोस्ट-प्रोडक्शन काम शुरू हो चुका है। कमल हासन एक बार फिर इस फिल्म में अपने महाहूर किरदार सेनापति के रूप में नजर आएंगे। फिल्म के निर्माताओं ने इसकी पुष्टि कर दी है कि 'इंडियन 3' पर काम शुरू हो गया है। फिल्म की कहानी और निर्देशन एस. शंकर ने किया है, जबकि कमल हासन मुख्य भूमिका में हैं। हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है। फिल्म के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर 'इंडियन 3' की वापसी का ऐलान किया। पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, 'सेनापति वापस आ गए हैं, जीरो टॉलरेंस के साथ।' 'इंडियन 3: वॉर मोड' में वापसी शुरू। इसके साथ एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें कमल हासन के तीन अलग-अलग किरदार दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक किरदार सेनापति का है। फिल्म को लेकर क्यों बनी थी असमंजस की स्थिति

'इंडियन 3' को शुरू से ही 'इंडियन 2' की कहानी का संधि अगला हिस्सा माना गया था। दोनों फिल्मों के कई हिस्सों की शूटिंग एक साथ की गई थी। 'इंडियन 2' के अंत में भी 'इंडियन 3' की झलक दिखाई गई थी। इसमें सेनापति के अतीत की कहानी की तरफ इशारा किया गया था और उनके पिता वीरसेकरन बालराम के किरदार को भी पेश किया गया था। लेकिन जुलाई 2024 में रिलीज हुई 'इंडियन 2' उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। करीब 250 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म को इसकी कहानी और प्रस्तुति के लिए काफी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। यह 2024 की बड़ी बजट वाली असफल फिल्मों में भी शामिल रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में करीब 148-151 करोड़ रुपये की कमाई की। फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई में भी जल्द गिरावट देखने को मिली।

'द ट्रेटर्स तेलुगु' की लेकर बोले तेजा सज्जा

तेलुगु सिनेमा के अभिनेता तेजा सज्जा अब एक बिल्कुल नए अंदाज में दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार हैं। वह जल्द ही स्ट्रीमिंग रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स तेलुगु' को होस्ट करते नजर आएंगे। शो का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज किया गया, जिसमें तेजा सज्जा की होस्ट के तौर पर झलक देखने को मिली। शो में अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े 20 सेलिब्रिटीज हिस्सा ले रहे हैं और इनके बीच भरतेश, झुठ, रणनीति और हिमांगी खेल का मुकाबला देखने को मिलेगा। 'द ट्रेटर्स तेलुगु' अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महाहूर फॉर्मेट का पहला तेलुगु एडिशन है। शो में चिन्मयी श्रौपदा, हर्ष वर्धन, प्रगति महावाडी, श्रीदेवी चौधरी, निखिल विजयेंद्र सिम्हा, विद्या रमन, विष्णु ओई, ब्राह्म वरमा, डॉ. मेनाथ रेड्डी, मोनीषा चौधरी, स्वीकर अगस्त्य, आशिश पद्मकाण, वर्षा डी 'सुजा, प्रणव उर्फ अभिनवकावि, एक्स्स वर्धन, राहत अवता, गौरव सुनील, साई रोकन, पुष्पला धनंजय और फल्गुनी बांगेज नजर आएंगे।



35 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनेंगी कियारा आडवाणी

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर एक बार फिर नन्हें मेहमान की किलकारी गुंजने वाली है। कपल ने बुधवार सुबह अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर इस बात की जानकारी सभी के साथ शेयर की। पोस्ट खमने आते ही फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स कपल को जमकर बधाई दे रहे हैं। कियारा आडवाणी ने इंस्टाग्राम पर पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक जॉइंट पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में एक तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें कपल के हाथ पर एक छोटे बच्चे के सॉक्स रखे हैं और उनकी बेटी सराया ने भी उसे पकड़ रखा है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, 'एक बार फिर सबसे बड़े तोहफे का आशीर्वाद मिला है। हमारा दिल प्यार और शुक्रगुजार से भरा हुआ है।' कियारा और सिद्धार्थ के पोस्ट पर रकुलप्रीत सिंह ने लिखा, 'वह, यह बहुत अच्छी खबर है।' इनके अलावा करण जोहर, परिणीति चोपड़ा, अधिया शेट्टी, भूमि पेडनेकर, करीना कपूर और मसाबा गुप्ता समेत कई हस्तियों ने बधाई देते हुए अपना प्यार लुटाया। 2025 में दिया था बेटी सराया को जन्म बता दें कि कियारा और सिद्धार्थ ने शादी के लगभग दो साल बाद जुलाई 2025 में बेटी सराया मल्होत्रा का स्वागत किया था। अब सराया के जन्म के डेढ़ साल बाद यह कपल फिर माता-पिता बनने वाले हैं। सलमान ने सिद्धार्थ से कही थी ये बात कुछ समय पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा 'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार एपिसोड में अपनी फिल्म 'द दन' को प्रमोट करने पहुंचे थे। उस दौरान अभिनेता ने सलमान खान के साथ पिता बनने के अनुभव को शेयर किया था। सिद्धार्थ ने कहा था कि पिता बनना उनके लिए सबसे बेहतरीन रोल है। उन्होंने बेटी सराया अब करीब 15 महीने की हो चुकी है और अब वह नई चीजें सीख रही है। तभी सलमान खान ने मजाक में सिद्धार्थ से कहा था कि उम्मीद है कि वह जल्द ही एक और बेटी का वेलकम करेंगे।



यामी गौतम का 'नई नवेली' में दिखेगा सबसे अलग अवतार, बताया कैसे अपनाया है 'मोहिनी' का अलग अंदाज

अवस्थी परिवार में आपका स्वागत है; जहां ड्रामा है, मस्ती है और सबसे बढ़कर एक ज़खन का राज है! अमेज़न स्वरस्टूडियोज़ और कलर खेलों की फिल्म 'नई नवेली' की कहानी एक जाने-पहचाने भारतीय परिवार की झलक देती है। कहानी में एक आम परिवार की दुनिया बेहद दिलचस्प तरीके से बदल जाती है, और फिर इसमें लार्जर देन लाइफ किरदारों, परिवार में होने वाले मजाक और डेर सारे ट्विस्ट और टर्न के अलावा फेमिली डॉग के भी उस उथल-पुथल में शामिल हो जाने की झलक मिलती है। फेमिली, कॉमेडी, फेरेटीसी, मिस्ट्री और एक्शन को एक साथ मिलाते हुए फिल्म दर्शकों के सामने एक साथ मस्ती, ह्यूमर, इमोशन और बहुत सारे दिलचस्प सारप्राइज लेकर आती है। फिल्म की कहानी भारतीय परिवार के जड़ों से जुड़ी हुई है, और इस तरह से ये दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में लेकर जा रही है जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा है। हर नई परत के खुलने के साथ नई नवेली फिल्म अपनी तरह की इकलौती लार्जर देन लाइफ बिग स्क्रीन एडवेंचर बनकर इस दशहरा के मौके पर कुछ

अलग देने का वादा करती है। कहानी के केंद्र में नेशनल अवॉर्ड विनर यामी गौतम घर मोहिनी के किरदार के साथ एक बेहद अलग अवतार में नजर आने वाली हैं। ज़बरदस्त लुक से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक, उनकी कॉमिक विलस और एक्शन किरदार में सेस ऑफ सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। एक इवेंट में यामी ने अपने रोल के बारे में और उसकी तैयारी करने के प्रोसेस पर बात की कि कैसे उन्होंने मोहिनी को एक पूरी तरह से नई पर्सनालिटी बनाई है। उन्होंने साझा करते हुए कहा, हर रोल अपने साथ एक नए चैलेंज और डिमांड लाता है। जब भी कोई मुझसे किसी रोल की तैयारी के बारे में पूछता है, तब मैं उस याद में चली जाती हूँ, जब मैंने पहली बार उस रोल के बारे में सुना था पढ़ा था। यामी ने कहा, तब आपको फहसास होता है कि मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन आपको बहुत सी चीजें भी सीखनी पड़ती हैं, जैसे रिकवर्स, एक्शन, और बॉडी लैंग्वेज। यह ऐसा है जैसे आपको अपने सामने एक पेरिलस पर्सनालिटी बनानी है और फिर उसे अपनी रिकन की तरह पहनना है, वही इंसान बनना है।

आगे बात करते हुए वे कहती हैं, मैं ऐसी स्ट्रेंट हूँ जो हमेशा सोचती रहती हूँ कि तैयारी में कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। मेरा मानना है कि आप जितनी बार स्क्रीन पढ़ते हैं, उतना ही आपको अपने किरदार या कहानी में कुछ नया जोड़ने का मौका मिलता है। फिल्म की नवरा समझना बहुत जरूरी है। मोहिनी उसी तरह नहीं हसेगी, जैसे मैंने अपनी दूसरी फिल्मों में निभाए किरदारों में हंसी है। मैं अपने हर किरदार में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट, कुछ नया जोड़ने की कोशिश करती हूँ, ताकि ऑडियंस को भी उसे देखने में मजा आए। यामी गौतम घर स्टार इस फिल्म को बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया है, जबकि इसकी कहानी हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है। फिल्म में अभिनाथ एम. कोठार, अनुराग ठाकुर, सुनीता राजवार, मीता वशिष्ठ, आदित्य कुलश्रेष्ठ, सुमिता मुखर्जी और प्रतीक पब्तरी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। जबकि, इसे आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। यह फिल्म इस दशहरा, 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।



कलिंग समाचार



संपादकीय

विदेश नीति को बदलते प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इतिहास में अपना नाम किन अक्षरों में दर्ज कराना चाहते हैं, ये तो पता नहीं, लेकिन भारत की विदेश नीति का जो गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास रहा है, उसे वो पूरी तरह मटियामेट करना चाहते हैं, यह साफ नजर आ रहा है। वैसे भी जब इतिहास की पूरी समझ न हो, या जानबूझकर इतिहास को नजरंदाज किया जाता है तो वर्तमान और भविष्य दोनों किस तरह खतरे में पड़ जाते हैं, इसका बड़ा उदाहरण नरेन्द्र मोदी की इजरायल यात्रा से मिल ही रहा है। महज दो दिनों के लिए मोदी इजरायल गए, लेकिन वहां जो कुछ उन्होंने कहा, उससे भारत की बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया है। इजरायली संसद नेसेट में जिस तरह का भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, उसमें वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि इजरायल ने फिलीस्तीन में हमास को खत्म करने के नाम पर जो नरसंहार किया, उस पर दुनिया भर में चिंता जाहिर की जा रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इजरायली संसद में जाकर हमास की न केवल आलोचना की, बल्कि तीन साल पहले 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले की तुलना भारत में मुंबई के आतंकी हमले से कर दी। माना कि दोनों में निर्दोष लोगों की ही जान गई, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि नरेन्द्र मोदी को यूपीए सरकार में हुआ मुंबई हमला अगर याद आया तो खुद की सरकार में हुए पुलवामा और पहलगाम जैसे बड़े आतंकी हमलों को वो कैसे भूल गए। होता तो यही है कि इंसान को हाल की बात पहले याद आती है और पुरानी बात बाद में। लेकिन मोदीजी के साथ उल्टा ही हो रहा है। उन्हें अपने कार्यकाल का कुछ याद नहीं रहता, केवल कांग्रेस की सरकारों की बातें याद पड़ती हैं। अपने संबोधन में मोदी ने ग़ज़ा शांति पहल को क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में एक रास्ता बताया। यानी सीधे-सीधे अमेरिका की तारीफ उन्होंने की। इसके साथ ही इजरायल के साथ एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि कहीं भी आतंकवाद शांति को हर जगह खतरे में डालता है। गौर कीजिए कि मोदी ने इजरायल की कुर्बानियों का ज़ि़क्र किया लेकिन ग़ज़ा में मारे गए 70 हज़ार लोगों की हत्या और हमदर्दी के लिए एक शब्द नहीं कहा, वो कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें तो ट्रंप और नेतन्याहू से दोस्ती निभानी है। मोदी ने ग़ज़ा नरसंहार को पूरी तरह नज़रन्दाज़ किया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन दुख इस बात का है कि अपने साथ-साथ उन्होंने पूरे देश की जनता को इजरायल के साथ खड़ा दिखाया। मोदी ने कहा, %में भारत की जनता की ओर से हर खोई हुई जान के लिए गहरी संवेदना लेकर आया हूं और हर उस परिवार के लिए जिनका संसार 7 अक्टूबर 2023 को हमास के बर्बर आतंकवादी हमले में टूट गया। हम आपका दर्द महसूस करते हैं। हम आपका दुख साझा करते हैं। भारत इजरायल के साथ मजबूती से, पूरे विश्वास के साथ, इस पल में और उसके आगे भी खड़ा है। कोई भी कारण नागरिकों की हत्या को जायज नहीं ठहरा सकता। कुछ भी आतंकवाद को जायज नहीं ठहरा सकता। कितने सुविधाजनक तरीके से मोदी ने ग़ज़ा में नेतन्याहू के इजरायली आतंकवाद का ज़ि़क्र तक नहीं किया। जबकि खुद इजरायल की जनता अपनी सरकार के ऐसे बर्बर रवैये के खिलाफ है। उन्हें अपने कार्यकाल का कुछ याद नहीं रहता, केवल कांग्रेस की सरकारों की बातें याद पड़ती हैं। अपने संबोधन में मोदी ने ग़ज़ा शांति पहल को क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में एक रास्ता बताया। यानी सीधे-सीधे अमेरिका की तारीफ उन्होंने की। इसके साथ ही इजरायल के साथ एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि कहीं भी आतंकवाद शांति को हर जगह खतरे में डालता है। गौर कीजिए कि मोदी ने इजरायल की कुर्बानियों का ज़ि़क्र किया लेकिन ग़ज़ा में मारे गए 70 हज़ार लोगों की हत्या और हमदर्दी के लिए एक शब्द नहीं कहा, वो कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें तो ट्रंप और नेतन्याहू से दोस्ती निभानी है।

आयातित विदेशी हथियारों पर भारत की निर्भरता चिंता की बात

नन्तू बनर्जी
भारत अभी भी चीन और पाकिस्तान जैसे बहुत ज्यादा लड़ाकू पड़ोसियों से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए बहुत ज्यादा विदेशी आयात पर निर्भर है। स्वदेशीकरण के तथाकथित दबाव के बावजूद, भारत, चीन और पाकिस्तान से दोहरे खतरों का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी प्रौद्योगिकी, जेट और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी काफी हद तक विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की फ़्रांस से 114 राफेल फ़ाइटर जेट खरीदने की नई मंजूरी से ज़्यादा उत्साहित होने की कोई बात नहीं है, जिसकी कीमत 3.25 लाख करोड़ रुपये (लगभग 40 अरब डॉलर) है, जिसे %सभी डिफेंस डील्स की सबसे बड़ी डील% कहा जा रहा है। यह बड़ी चिंता की बात है कि देश की आज़ादी के 78 साल बाद भी, यूक्रेन की तरह भारत को भी अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए आयातित हथियारों पर निर्भर रहना पड़ता है- फ़्रांस से राफेल, संयुक्त राज्य अमेरिका से पोसाइडनजेट, और रूस से एस-400ट्राय फ जैसे कई दूसरे हथियार। यहां तक कि उन क्षेत्रों जहां भारत विदेशी सहयोग से रक्षा उपकरण बना रहा है, में भी देश अभी भी विदेशी सबसिस्टम पर बहुत ज्यादा निर्भर है। हालांकि एयरक्रा ट और जहाज़ जैसे प्लेटफॉर्म भारत में असेंबल किए जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी हाई-एंड कंपोनेंट अभी भी आयातित किए जाते हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हो जाती है। पिछले कुछ सालों में, भारत ने कई राफेल सौते किए हैं। इनमें लगभग 7.87 अरब यूरो (लगभग 58,891 करोड़ रुपये) के 36जेट शामिल हैं और हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए 26 नेवल वेरिएंट के सौदे हुए हैं, जिसकी कीमत 64,000 करोड़ रुपये है। भारत में बने जेट के साथ क्वालिटी एश्योरेंस के मुद्दों पर कई सालों तक बातचीत चलने के बाद भारत ने 2015 में फ़्रांस से 126 राफेल फाइटर खरीदने के समझौते को रद्द कर दिया था। 1950 में, पड़ोसी चीन की अर्थव्यवस्था और रक्षा भारत की तुलना में बहुत कमजोर थी। आज, चीन खुद को अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की सबसे सेल्फ-प्रोपेल्ड घातक मिलिटरी ताकतों में से एक मानता है। भारत के आयात पसंद करने वाले राजनीतिक शासकों की वजह से, देश को एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नालॉजी, खासकर जेट इंजन, एंकिटव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्डरे (ईईएसए) रडार, मिसाइल सीकर और स्टील्थ टेक्नालॉजी विकसित करने में बड़ी कमियों

का सामना करना पड़ रहा है। भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास खर्च दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। डीआरडीओ को 2025–26 में कुल रक्षा बजट का सिर्फ 3.94 प्रतिशत मिलेगा। लंबे खरीद चक्र और आर एंड डी परियोजनाओं में बहुत ज्यादा देरी से आधुनिकीकरण में रुकावट आ रही है। भारत के पास यूएवी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए काफी, विश्व स्तरीय परीक्षण अवसंरचना भी नहीं है, जिससे देशी उत्पादनों के विकास और प्रमाणीकरण में कमी आ रही है।

भारत के लगभग 80 प्रतिशत रक्षा उपकरण रूस के होने के कारण, रूस देश की रक्षा क्षमताओं का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। रूस तब सामने आया जब पश्चिमी मिलिटरी ताकतों ने भारत को हाई-एंड हथियार आपूर्ति करने से लगभग मना कर दिया था। भारत-रूस रक्षा भागीदारी सिर्फ खरीदार-विक्रेता संबंध से बढ़कर संयुक्त विकास और उत्पादन तक फैली हुई है। भारत में मौजूद बड़े खतरनाक रूसी प्लेटफॉर्म में सुखोई एसयू-30एमकेआई (जो रूस की मदद से भारत में बना), टी-905 %भीष्म’ और टी-22मु य लड़ाकू टैंक, ब्रह्मोसक् रूज़

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के अप्रत्याशित विजेता हैं राहुल गांधी

के रवींद्रन

आखिरकार, गांधी की राजनीतिक विश्वसनीयता में बढ़ोतरी एक ज़रूरी सच्चाई को दिखाती है= लोकतांत्रिक राजनीति में, असहमति- जब पक्षे यकीन और असर के साथ कही जाए- तो नेताओं को ऊपर उठा सकती है और बहस को नई दिशा दे सकती है। यह पल भारतीय राजनीति में एक स्थायी मोड़ बनेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और विपक्ष दोनों इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के आस-पास चल रही राजनीतिक कहानी ने टैरिफ, बाजार में पहुंच और राजनयिक गठजोड़ पर बहस छोड़ने से कहीं ज़्यादा असर डाला है। इसने भारत के घरेलू राजनीतिक माहौल की रूपरेखा को बदल दिया है, खासकर राहुल गांधी का कद मु य विपक्षी नेता के तौर पर बढ़ाकर। मोदी सरकार ने व्यापार समझौते को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया है, जो 30 ट्रिलियन डालर के अमेरिकी बाजार में खास पहुंच की रणनीतिगत और आर्थिक मूल्य को दिखाता है।

इस समझौते के फ़ायदों को बताते हुए, मोदी प्रशासन एक बड़ा दावा कर रहा है= कि भारत के लंबे समय के आर्थिक फ़ायदे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा करीब से जुड़ने से ही सबसे अच्छे ढंग से पूरे होंगे। कई खरब डॉलर के बाजार पर ज़ोर, आकांक्षा और विकास की एक लोकलुभाऊ कहानी को दिखाता है। फिर भी, इस कहानी को बिना चुनौती दिए नहीं छोड़ा गया है। राहुल गांधी की इस समझौते की जोरदार आलोचना, जिसमें उनकी भावनाओं और राजनीतिक संवेदनाएं जुड़ी हैं

– और जिसमें उनका यह कहना कि यह %भारत माता’ को बेचने जैसा है, ने एक तकनीकी नीति चर्चा को राष्ट्रीय पहचान, स प्रभुता और राजनीतिक नेतृत्व पर एक बड़े मुकाबले में बदल दिया है। खास बात सिर्फ गांधी की आलोचना का तथ्य ही नहीं है, बल्कि उसे मिली राजनीतिक पकड़ भी है। पारंपरिक रूप से, इस कांग्रेस नेता को कई जानकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक दबदबे के मुकाबले कम मजबूत विरोधी के तौर पर दिखाया है। हालांकि, व्यापार समझौते पर उनके रुख ने भद्रलोक के राजनीतिक दायरे और आम जनता के कुछ हिस्सों में भी इस सोच को बदल दिया है। सरकार के तौर-तरीके को जोरदार ढंग से चुनौती देकर, गांधी ने राष्ट्रीय गौरव और आर्थिक बराबरी को लेकर बुनियादी चिंताओं को छुआ। उनकी टिप्पणी उन लोगों को पसंद आई जो वैश्वीकरण के अलग-अलग फ़ायदों से सावधान थे और उन समझौतों पर शक करते थे जिन्हें भद्रलोक के हितों के लिए या राणनीतिगत स्वायत्तता से समझौता करने वाला माना जाता था। ऐसा करके, उन्होंने बहस को व्यापारिक घाटे और टैरिफ लागू किये जाने की निर्धारित अवधि तक सीमित न रखकर इस बड़े सवाल से जोड़ दिया कि भारत का आगे का रास्ता कौन तय करेगा।

गांधी की आलोचना पर सरकार की प्रतिक्रिया जोरदार और बिना रुके रही है। सत्ताधारी पार्टी की मशीनरी, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि, पार्टी के प्रवक्ता और उससे जुड़े मीडिया शामिल हैं, ने समझौते के उनके विरोध को बदनाम करने के लिए कमर कस ली है। यह बचाव का रवैया न केवल एक तीखे राजनीतिक जवाब का संकेत देता है, बल्कि गांधी की बढ़ती पहचान के नतीजों को लेकर

एक बड़ी चिंता का भी संकेत देता है। उन्हें गैर-ज़िंमेदार या देशद्रोही बताने की उनकी लगातार कोशिशें इस बात की जानकारी दिखाती हैं कि गांधी की आलोचना ने सरकार की शुरुआती सोच को तोड़ दिया है और एक ज़्यादा विवादित सार्वजनिक बातचीत को मजबूर किया है।

इस प्रक्रिया में, गांधी की राजनीतिक विश्वसनीयता को काफी बढ़ावा मिला है। एक मामूली या बेअसर विपक्षी नेता के तौर पर खारिज किए जाने के बजाय, अब वह सरकार की एक अहम नीतिगत उपलब्धि के बारे में हो रही बातचीत में एक केन्द्रीय जगह पर हैं। एक तरफ, इसने ऐसे समय में विपक्ष की आवाज़ को और तेज़ कर दिया है जब सरकार को अपनी विदेश नीति पहल पर बड़ी आम सहमति की उ मीद थी। दूसरी तरफ, इसने आ यान पर सरकार के नियंत्रण की सीमा को भी सामने ला दिया है। भारत-अमेरिका समझौते के फायदों को जोर-शोर से आगे बढ़ाकर, मोदी प्रशासन का मकसद

ट्रंप का असली चेहरा सामने आया

शांति का नोबेल पुरस्कार हासिल करने की तमन्ना लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने %ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व% चलाकर वेनेजुएला पर शनिवार स्थानीय समय के अनुसार 02ऽ01 बजे हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सिलिया लोरेस समेत गिर तार कर लिया और उन्हें हवाई मार्ग से अमेरिका ले आया गया। अमेरिकी विमान से मादुरो को जब उतारा जा रहा था तो उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हथकड़ियां भी लगी थीं। यह दृश्य देखकर इतिहास खुद को दोहराता है, वाली मिसाल याद आ गई। लेकिन यह नहीं पता

देरी होती है। शुरु में, चीन भी रूसी रक्षा आपूर्ति पर निर्भर था। लेकिन, क युनिस्ट शासन ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बहुत प्राथमिकता दी और सालों से रक्षा उत्पादनों की हाई-एंड मैनुफ़ैक्चरिंग के लिए दुनिया भर में एक बड़ा दावेदार बन गया।

चीन का एक लो-टेक हथियार आयातक से एक हाई-एंड देशी डिफेंस मैनुफ़ैक्चरर और निर्यातक बनना एक लंबे समय की, सरकार की बनाई रणनीति से हुआ है, जिसमें अनुसंधान और विकास में भारी निवेश, इंटेस मिलिट्री-सिविल यूजन (एमसीएफ), और विदेशी प्रौद्योगिकी का लक्षित प्रदर्शन शामिल है। पिछले दस सालों में, चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बनकर उभरा है, जिसके पास स्टील्थ फाइर्ट्स (जे-20, जे-35), एयरक्रा ट कैरियर (फुजियान), और हाइपरसोनिक मिसाइलों की क्षमता है जो पश्चिमी प्रौद्योगिकी की बेहतरी को चुनौती देते हैं।

तकनीक गाइड स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिप्री) के वैश्विक हथियारों के हस्तान्तरण, निर्यात मात्रा और अतिविकसित सैन्य प्रौद्योगिकी के विकास के आंकड़े के आधार पर, हाई-एंड डिफेंस इक्षिपमेंट (2020–2024) बनाने वाले सर्वोच्च

हैसियत को और मजबूत करने से उल्टा पड़ सकता है। सरकार के लिए खतरा यह है कि उनकी आलोचना को कम करने की कोशिश में, वे अनजाने में उसे सही ठहराते हैं। इस मुद्दे पर राहुल गांधी को बार-बार लक्षित करने से वे विरोध का केंद्र बन सकते हैं, और ऐसे समर्थकों को बढ़ावा मिल सकता है जो उनके विरोध को मौकापरस्त के बजाय उसूलों पर आधारित मानते हैं। ऐसे राजनीतिक माहौल में जहां राष्ट्रवाद और आत्मनिर्णय की बातें काफी मायने रखती हैं, और राहुल गांधी को किसी विदेशी ताकत को दी जा रही कथित छूट के खिलाफ भारत की ईज़्जत के रक्षक के तौर पर पेश करने के दूरगामी असर हो सकते हैं। इस राजनीतिक नाटक का बड़ा मतलब यह है कि आर्थिक राजनयिकता को घरेलू वैधता से अलग नहीं किया जा सकता। भारत-अमेरिका समझौते पर बहस यह दिखाती है कि कैसे वैश्विक आर्थिक नीतियां राष्ट्रीय चरित्र, नेतृत्व की विश्वसनीयता, और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के

असली चेहरा सामने आया

हथियाने का आरोप लगाने के साथ ड्रस तस्करी के गंभीर आरोप भी लगाए हैं और उनका कहना है कि अब मादुरो को पत्नी समेत अमेरिका की कड़ी न्याय व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा।

मानो सारी दुनिया का ठेका अमेरिका को मिल चुका है कि उसका राष्ट्रपति जब चाहे किसी संप्रभु देश पर आक्रमण कर दे और वहां के नेता को अमेरिकी कटघरे में खड़ा कर दे। और अंतरराष्ट्रीय कानूनों, स्त्री अधिकार को ठेंगा दिखाते हुए राष्ट्र प्रमुख के साथ उनकी पत्नी को भी गिर तार कर ले। चिंता की बात यह है कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जिन उद्देश्यों

10 देशों में एयरोस्पेस, नेवल और मिसाइल प्रौद्योगिकी में भारी निवेश करने वाली बड़ी ताकतें सबसे ज़्यादा हैं। ये देश हैं=यूनाइटेड स्टेट्स, फ़्रांस, रूस, चीन, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, स्पेन और साउथ कोरिया।

हालांकि, भारत अभी भी चीन और पाकिस्तान जैसे बहुत ज्यादा लड़ाकू पड़ोसियों से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए बहुत ज्यादा विदेशी आयात पर निर्भर है।

स्वदेशीकरण के तथाकथित दबाव के बावजूद, भारत, चीन और पाकिस्तान से दोहरे खतरों का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी प्रौद्योगिकी, जेट और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी काफी हद तक विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। यह निर्भरता सीमा विवाद, सीमा पार से आतंकवाद और अस्थिर पड़ोसी के साथ बनी हुई है। जबकि 3,488 किलो मीटर भारत-चीन सीमा (एलएसी) पर तनाव सालों से बना हुआ है, पाकिस्तान से भी सीमा-पार आतंकवाद के लिए लगातार तैयार रहने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हाई-एंड घरेलू रक्षा विनिर्माण में बड़ा निवेश करे। हाई-एंड सैन्य प्रौद्योगिकी में अंतर को कम करना अब देश के लिए एक असली चुनौती है।

सवालों से अलग नहीं हो सकती। मोदी सरकार के लिए, अमेरिकी बाजार में खास पहुंच पाना एक रणनीतिगत प्राथमिकता बनी हुई है। राहुल गांधी के लिए, उसी समझौते की आलोचना ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का एक अनोखा मौका दिया है। आखिरकार, गांधी की राजनीतिक विश्वसनीयता में बढ़ोतरी एक ज़रूरी सच्चाई को दिखाती है= लोकतांत्रिक राजनीति में, असहमति- जब पक्षे यकीन और असर के साथ कही जाए- तो नेताओं को ऊपर उठा सकती है और बहस को नई दिशा दे सकती है। यह पल भारतीय राजनीति में एक स्थायी मोड़ बनेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और विपक्ष दोनों इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अभी के लिए, राजनीतिक मैदान में सबसे ज़्यादा फ़ायदा राहुल गांधी को मिल रहा है, जिनकी समझौते को चुनौती ने उनकी आवाज़ को और मजबूत किया है और राष्ट्रीय बातचीत में उनकी भूमिका को नया रूप दिया है।



विविध समाचार



आपातकाल के दौरान जेलें काटने वाले संघर्षशील योद्धाओं को एमपी और हरियाणा की भाजपा सरकार की तरह पेंशन दे मान सरकार : हरदेव सिंह उम्मा

चंडीगढ़ : भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश प्रेस सचिव हरदेव सिंह उम्मा ने कहा है कि देश में आपातकाल के दौरान जेलें काटने वाले संघर्षशील योद्धाओं के साथ पंजाब सरकार द्वारा लगातार अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले इन

योद्धाओं को आज तक उनका उचित सम्मान और पेंशन नहीं मिली। उम्मा ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में आपातकाल संघर्षशील योद्धाओं के लिए पेंशन योजनाएँ लागू हैं, लेकिन पंजाब में इस मामले को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन

संघर्षशील योद्धाओं ने जेलों में वर्षों तक कष्ट सहें, वे आज भी बुजुर्ग अवस्था में दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं।

भाजपा नेता हरदेव उम्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश और हरियाणा की भाजपा सरकार की तरह भगवंत मान सरकार भी 30 हजार रुपये प्रति माह पेंशन दे। हरदेव सिंह उम्मा ने कहा कि

विभिन्न राज्यों में आपातकाल योद्धाओं को 10 हजार से 30 हजार रुपये तक पेंशन दी जा रही है, लेकिन पंजाब सरकार ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि वह केवल वादे कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया। हरदेव सिंह उम्मा ने मांग

की कि पंजाब सरकार तुरंत आपातकाल संघर्षशील योद्धाओं के लिए पेंशन योजना लागू करे और उन्हें उनका बनता सम्मान प्रदान करे। उन्होंने कहा कि भाजपा आपातकाल संघर्षशील योद्धाओं के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आवाज बुलंद करती रहेगी।

राष्ट्रीय युवा दिवस पर सुखना लेक में ‘विकसित भारत मैराथन’ का आयोजन

चंडीगढ़ : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) एवं विद्यार्थी कल्याण ट्रस्ट की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर ‘विकसित भारत’ की संकल्पना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सुखना लेक, चंडीगढ़ में ‘विकसित भारत मैराथन’ का आयोजन किया गया। मैराथन में चंडीगढ़ के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से 1,500 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया और युवाओं से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में सक्रिय

भूमिका निभाने का आह्वान किया। मैराथन का शुभारंभ राज्यसभा सांसद श्री सतनाम सिंह संधू और एबीवीपी पंजाब प्रांत अध्यक्ष प्रो. प्रशांत गौतम ने हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं में अनुशासन, राष्ट्रप्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं तथा ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को साकार करने में सहायक हैं। इस आयोजन के मुख्य प्रायोजक राज मल्होत्रा आईएस अकादमी और वीटा रहे जिनके सहयोग से कार्यक्रम का सफल आयोजन संभव हो सका। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री आदित्य तक्रियार ने कहा कि पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला।

डबल इंजन सरकार किसानों के सम्मान व सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध : नायब सिंह सैनी



चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दीनबंधु चौधरी छोटूराम के संघर्षों से किसान और मजदूर के जीवन में निर्णायक बदलाव आया। कृषि भूमि की रक्षा किसान की गरिमा और मेहनतकश की इज्जत उनके जीवन के मूल मंत्र थे। इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए डबल इंजन सरकार किसानों के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को कुरुक्षेत्र स्थित अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी तथा सांसद सुभाष बराला ने दीनबंधु सर छोटूराम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला को 31 लाख रुपये तथा सांसद सुभाष बराला ने 21 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी और दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका जीवन साहस, संवेदना और सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने किसानों को साहूकारों के शोषण से मुक्त कराने के लिए प्रभावी कानून बनाए और अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। प्रदेश में 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। सरकार ने अब तक फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपये किसानों को दिए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20 लाख से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक-2024 पारित कर पट्टेदार किसानों को कानूनी सुरक्षा दी गई है। ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है।

गोल्डन टेंपल सरोवर में कुल्ला करने वाले को निहंगों ने जड़ा थप्पड़, माफी मंगवाकर पुलिस को सौंपा

अमृतसर/गाजियाबाद । अमृतसर के स्वर्ण मंदिर (गोल्डन टेंपल) के पवित्र सरोवर में कुल्ला करने और उसका वीडियो वायरल करने वाले मुस्लिम युवक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शनिवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में निहंग सिखों ने उक्त युवक को पकड़ लिया। निहंग विक्की थॉमस की मौजूदगी में युवक का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उसे एक निहंग द्वारा थप्पड़ जड़ते हुए देखा गया। निहंगों ने युवक और वीडियो बनाने वाले उसके साथी को

पकड़कर सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। इसके बाद निहंगों ने उसे गाजियाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और अब उसे अमृतसर पुलिस को सौंपने की तैयारी की जा रही है।

इस मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी अब सख्त रुख अपनाते हुए अमृतसर पुलिस के पास औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी है। SGPC ने जब अपने स्तर पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मामले की जांच की, तो बेहद चौंकाने

वाली बात सामने आई। जांच में पता चला कि आरोपी युवक करीब 20 मिनट तक गोल्डन टेंपल परिसर में मौजूद रहा, लेकिन इस दौरान उसने एक बार भी परिक्रमा नहीं की और न ही गुरु घर में माथा टेकने की कोशिश की। SGPC का कहना है कि उसका व्यवहार और गतिविधि गंभीरता से लेकर देखा जा रहा है। जांच में पता चला कि आरोपी युवक करीब 20 मिनट तक गोल्डन टेंपल परिसर में मौजूद रहा, लेकिन इस दौरान उसने एक बार भी परिक्रमा नहीं की और न ही गुरु घर में माथा टेकने की कोशिश की। SGPC का कहना है कि उसका व्यवहार और गतिविधि गंभीरता से लेकर देखा जा रहा है। जांच में पता चला कि आरोपी युवक करीब 20 मिनट तक गोल्डन टेंपल परिसर में मौजूद रहा, लेकिन इस दौरान उसने एक बार भी परिक्रमा नहीं की और न ही गुरु घर में माथा टेकने की कोशिश की। SGPC का कहना है कि उसका व्यवहार और गतिविधि गंभीरता से लेकर देखा जा रहा है।

बार उसने जेब में हाथ डालकर माफी मांगी थी और दूसरी बार भी उसका रवैया समुदाय को नागवार गुजरा था। वहीं, इस मामले में शुरुआत में कोई ठोस कानूनी कार्रवाई न करने पर SGPC की भी कड़ी आलोचना हो रही थी। संगत का सवाल था कि जब गुजरात की अर्चना मकवाना द्वारा योग करने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है, तो सरोवर की मर्यादा भंग करने वाले इस युवक पर नरमी क्यों बरती गई। इसी ढिलाई को देखते हुए निहंगों ने पहले गाजियाबाद प्रशासन को शिकायत दी थी। गाजियाबाद में युवक को

पकड़ने के बाद निहंगों ने स्पष्ट किया कि युवक की हरकत से सिखों की धार्मिक भावनाएं बुरी तरह आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर सिख समुदाय पर जोश में आकर कानून हाथ में लेने के आरोप लगते हैं, इसलिए उन्होंने संयम बरतते हुए सबसे पहले कानून के दायरे में रहकर पुलिस से संपर्क किया। निहंगों की मांग थी कि युवक सार्वजनिक रूप से सिख मर्यादा के अनुसार अपनी गलती स्वीकार करे। फिलहाल गाजियाबाद के अंकुर विहार थाने की पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पंजाब में पूर्व महिला सरपंच की गोली मारकर हत्या, पति बाल-बाल बचा, पुरानी रंजिश में पड़ोसियों पर फायरिंग का आरोप

मानसा : पंजाब के मानसा जिले में शनिवार को दिनदहाड़े हुई एक वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। गांव खिल्लन में आपसी रंजिश का एक खौफनाक अंजाम देखने को मिला, जहां पूर्व महिला सरपंच की संरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने का आरोप किसी और पर नहीं, बल्कि उनके पड़ोसियों पर ही लगा है। मृतका की पहचान 45 वर्षीय महेंद्रजीत कौर के रूप में हुई है। हमलावरों ने न केवल महिला को निशाना बनाया बल्कि उनके पति पर भी जानलेवा हमला किया, लेकिन खुशकिस्मती से गोली गाड़ी में लगने की वजह से उनकी जान बच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना उस समय हुई जब पूर्व सरपंच महेंद्रजीत कौर अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी काम से जा रही थीं। इसी दौरान पीछे से आए हथियारबंद हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां लगने से महेंद्रजीत कौर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, उनके पति पर चलाई गई गोली निशाने से चूककर गाड़ी पर जा लगी,

जिससे वह बाल-बाल बच गए। दिनदहाड़े हुई इस गोलीबारी से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस की शुरुआती जांच और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, इस हत्या के तार पुरानी रंजिश से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार और आरोपी पक्ष (पड़ोसियों) के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इससे पहले भी पूर्व सरपंच के परिवार के एक सदस्य की हत्या की जा चुकी है, जिसके चलते इस घटना को गैंगवार या बदले की भावना से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक हत्या के पुख्ता कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन पुरानी दुश्मनी को ही मुख्य वजह माना जा रहा है। गोलीबारी की सूचना मिलते ही मानसा पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने खून से लथपथ पूर्व सरपंच के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और परिजनों के बयानों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है।

हर हिस्से में हवा और पानी के प्रदूषण की स्थिति

मध्य प्रदेश में देश के सबसे स्वच्छ शहर का कई बरसों से अवार्ड जीत रहे इंदौर में दूषित पानी पीने से एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई। साल का अंत और नए साल की शुरुआत इसी खबर से हुई है। पता नहीं चल पा रहा है कि पीने के पानी की सप्लाई में जहरीला पानी कहां से मिक्स हुआ। लेकिन खबर है कि दो महीने से लोग पानी के दूषित होने की शिकायत कर रहे थे। पानी से बदबू आ रही थी और लोगों की तबियत बिगड़ रही थी। अब खबर है कि पानी में एसिड और बैक्टीरिया की भारी मात्रा मिली है। लेकिन तय मानें कि इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। एकाध लोगों के तबादले होंगे और एकाध लोग निर्लंबित उसके बाद सब रफा दफा हो जाएगा। दूसरी खबर है कि राजधानी दिल्ली की, जहां पिछले ढाई महीने से हवा जहरीली बनी हुई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एज्युआई चार सौ के आसपास है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री का दावा है कि पिछले आठ साल में सबसे कम कम पीएम 2.5 पिछले साल यानी 2025 में रहा। उनके

हिसाब से एक ज्युबिक मीटर में पीएम 2.5 की मात्रा एक सौ के करीब है। सोचें, भारत सरकार का मानक प्रति ज्युबिक मीटर पीएम 2.5 की मात्रा 60 रखने का है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानक 12 का है। लेकिन एक सौ होने को उपलब्ध के तौर पर पेश किया जा रहा है। यह पूरे साल का औसत आंकड़ा है। पिछले ढाई महीने का औसत आंकड़ा तीन सौ से ऊपर का है। यह सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है देश के हर हिस्से में हवा और पानी के प्रदूषण की यही स्थिति है। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सात से आठ हमेशा भारत के होते हैं। सूची जितनी लंबी होती जाती है, भारत के शहरों की संख्या उतनी बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि भारत के उन शहरों में प्रदूषण है, जहां उद्योग लगे हैं। बिहार के ऐसे शहर, जहां दूर दूर तक कोई फैक्टरी नहीं है वहां भी एज्युआई चार सौ से ऊपर है और इसका कारण सिर्फ इतना है कि चारों तरफ धूल मिट्टी फैली है और निर्माण कार्यों से होने वाला प्रदूषण धूल की चादर की तरह फैला हुआ है। किसी भी शहर में नगर निगम को सफाई से कोई लेना देना नहीं है। राजधानी दिल्ली

में सैकड़ों टन कूड़ा रोज निकलता है, जिसका बड़ा हिस्सा सड़कों पर बिखरा रहता है। हर साल सर्दियों में कभी पटाखों पर तो कभी किसानों की पराली पर प्रदूषण का दोष मढ़ दिया जाता है। लेकिन अभी न तो पटाखे चल रहे हैं और न पराली जलाई जा रही है फिर भी एज्युआई चार सौ के करीब है। ये दो प्रतिनिधि घटनाएं हैं, जो बताती हैं कि भारत में प्रकृति कम आपदा पैदा कर रही है और व्यवस्था ज्यादा आपदा पैदा कर रही है। जहरीला पानी व्यवस्था से उपजी आपदा है तो दिल्ली का प्रदूषण भी व्यवस्था की वजह से है। गाड़ियों के अंधाधुंध रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। सड़क पर चलने की जगह नहीं है और न किसी के पास गाड़ी खड़ी करने की जगह है। लेकिन गाड़ियां निकल रही हैं और उनके धुएं से देश की हवा प्रदूषित हो रही है। सज्जिसडी के बाद भी ईवी गाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ रही है लेकिन जीएसटी में कटौती हुई तो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की बेतहाशा बिक्री हुई। देश के अलग अलग हिस्सों में हर साल बारिश के साथ भूस्खलन और हिमस्खलन की घटनाएं

हो रही हैं तो यह भी प्रकृति से ज्यादा मानवीय आपदा है। उज्जराखंड में टिहरी में पानी रोकने से बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं तो पहाड़ों में अंधाधुंध निर्माण और जंगलों की कटाई ने पहाड़ों को कमजोर किया है। दशकों से नदियों की सफाई नहीं होने से सभी नदियों में गाद जमी है, जिसकी वजह से नदियों में बारिश का पानी नहीं रूकता है और बाढ़ आती है। भारत की भीड़ किस तरह से कुव्यवस्था की गुलाम है इसका सबूत पिछले दिनों मिला, जब इंडिगो का संकट खड़ा हुआ। एक निजी कंपनी ने सरकार के आदेश का पालन नहीं करने का फैसला किया। उसने जरूरी संख्या में पायलट नहीं भरती किए और जब इयूटी के नए नियम लागू हुए तो उसने उड़ानें रद्द करनी शुरू की। उसने एक दिन में एक एक हजार उड़ानें रद्द की। पैसे और रसूख वाले लोग हवाईअड्डों पर भेड़ बकरियों की तरह घूम रहे थे। हजारों लोगों परितार के साथ कई कई दिन तक हवाईअड्डों पर फंसे रहे तो हजारों लोगों के बैगेज कई दिनों तक नहीं मिले। नागरिक असहाय तो सरकार भी असहाय।



खेत की सोलर फेंसिंग में फंसा मिला हाथी का शव, करंट से मौत की आशंका

सुंदरगढ २३/१० (संवाददाता): ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। जिले के बिसरा ज़्लॉक की बांधामुंडा पंचायत अंतर्गत डुमेरता गांव में बुधवार सुबह एक खेत में लगभग सात साल का हाथी मृत अवस्था में पाया गया। हाथी का शव खेत में लगी सोलर फेंसिंग यानी सौर ऊर्जा से संचालित बाड़ के तारों में फंसा हुआ था। इस स्थिति को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि हाथी की मौत बिजली का झटका लगने से हुई होगी। हालांकि, मौत के वास्तविक कारण की अभी पुष्टि नहीं हुई है। सूचना मिलने के बाद राउरकेला वन प्रभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार, घटना सुंदरगढ़ जिले के डुमेरता गांव की है। बुधवार सुबह एक खेत में हाथी का शव मिलने से मामला सामने आया। मृत हाथी की उम्र लगभग सात वर्ष बताई जा रही है। उसके दो दांत भी थे। हाथी खेत में लगाई गई सोलर फेंसिंग के तारों में फंसा हुआ मिला। इस कारण उसकी मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। शोक सांत्वना पाएं प्रारंभिक तौर पर बिजली का

झटका लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन वन विभाग ने अभी तक मौत के कारण की पुष्टि नहीं की है। दृष्टांत ऋद्धुस - आवारा कुत्ते की पीट-पीटकर हत्या बेंगलुरु में 3 आरोपी पकड़े गए घटना की जानकारी मिलने के बाद वन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिस्थितियों की जांच शुरू की। सोलर फेंसिंग के तारों में फंसा था हाथी इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हाथी का शव खेत में लगी सौर बाड़ के तारों में फंसा मिला। खेतों की सुरक्षा के लिए कई स्थानों पर सोलर फेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उद्देश्य जंगली जानवरों को फसलों तक पहुंचने से रोकना होता है। ऐसी प्रणालियों में सामान्यतः नियंत्रित विद्युत स्पंदन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें खेत से दूर रखा जा सके।

हालांकि, यदि किसी बाड़ में तकनीकी खराबी हो या उसे असुरक्षित तरीके से बिजली की आपूर्ति की जाए, तो वह जानवरों और मनुष्यों के लिए खतरनाक हो सकती है। डुमेरता गांव में लगी बाड़ की तकनीकी स्थिति ज्ञा थी, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। करंट लगने से मौत



की आशंका हाथी के सोलर फेंसिंग में फंसे मिलने के कारण उसकी मौत बिजली के झटके से होने की आशंका जताई जा रही है।

हालांकि, केवल तारों में फंसा शव मिलने से करंट लगने को मौत का निश्चित कारण नहीं माना जा सकता। यह पता लगाना जरूरी होगा कि घटना के समय बाड़ में बिजली प्रवाहित हो रही थी या नहीं। इसके अलावा बाड़ की वायरिंग, बिजली आपूर्ति और सुरक्षा उपकरणों की स्थिति भी महत्वपूर्ण हो सकती है। वन विभाग की जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि हाथी की मौत बिजली के झटके से हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण था। शोक सांत्वना पाएं राउरकेला वन प्रभाग की टीम पहुंची घटना की सूचना मिलते ही राउरकेला वन प्रभाग की टीम डुमेरता गांव पहुंची। वन

अधिकारियों ने हाथी की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है। जांच का मुख्य उद्देश्य मौत के वास्तविक कारण का पता लगाना है। अधिकारियों के सामने यह सवाल भी है कि हाथी सोलर फेंसिंग के संपर्क में कैसे आया और ज़्या बाड़ की व्यवस्था में कोई तकनीकी समस्या थी। हालांकि, वन विभाग की ओर से जांच के अंतिम निष्कर्ष अभी जारी नहीं किए गए हैं। मौत का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हाथी की मौत को लेकर फिलहाल कई संभावनाएं बनी हुई हैं।

शव जिस स्थिति में मिला है, उससे बिजली का झटका लगने की आशंका जरूर पैदा हुई है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष वैज्ञानिक और चिकित्सकीय जांच के आधार पर ही निकाला जा सकता है। वन्यजीवों की संदिग्ध मौत के

मामलों में पोस्टमार्टम और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे मौत के कारण और उससे जुड़ी परिस्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस मामले में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया और उसकी रिपोर्ट के संबंध में अभी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। हाथियों के लिए खतरा बन सकती है असुरक्षित बाड़ कृषि क्षेत्रों में जंगली जानवरों की आवाजाही रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की बाड़ लगाई जाती हैं। इनमें सौर ऊर्जा आधारित बाड़ भी शामिल हैं। सुरक्षा मानकों के अनुसार लगाई गई फेंसिंग का उद्देश्य जानवरों को दूर रखना होता है, न कि उन्हें गंभीर चोट पहुंचाना। लेकिन यदि किसी विद्युत बाड़ को गलत तरीके से लगाया जाए या उसमें अनधिकृत बिजली कनेक्शन जोड़ दिया जाए, तो

जानलेवा हादसे का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि, डुमेरता गांव की बाड़ में ऐसी किसी अनियमितता की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए जांच पूरी होने से पहले खेत मालिक या किसी अन्य व्यक्ति को ज़रूमेदार ठहराना उचित नहीं होगा। मानव-हाथी संघर्ष की चुनौती ओडिशा के कई वन क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही और कृषि भूमि के आसपास उनकी मौजूदगी एक महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रबंधन चुनौती रही है।

जंगलों के आसपास बसे गांवों में हाथी कभी-कभी भोजन और पानी की तलाश में खेतों तक पहुंच जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसानों को फसलों की सुरक्षा की चिंता रहती है, जबकि वन विभाग के सामने हाथियों और स्थानीय लोगों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती होती है। मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए सुरक्षित और वैज्ञानिक उपायों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना जाता है। डुमेरता गांव की घटना ने भी खेतों के आसपास वन्यजीव सुरक्षा के सवाल को सामने रखा है। सात साल के हाथी की मौत से चिंता शोक सांत्वना पाएं मृत हाथी की उम्र लगभग सात वर्ष बताई जा रही है। हाथियों का

जीवनकाल लंबा होता है और सात वर्ष की उम्र में वे विकास की अवस्था में होते हैं। इस उम्र के हाथी की मौत वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से चिंताजनक है। हाथी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वन क्षेत्रों में बीजों के फैलाव और प्राकृतिक वनस्पति के विकास में योगदान देते हैं। इसलिए हाथियों की असामान्य मौत के मामलों की गंभीरता से जांच करना आवश्यक है। खेतों की सुरक्षा के साथ वन्यजीव संरक्षण जरूरी कृषि भूमि को जंगली जानवरों से बचाना किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले उपाय ऐसे होने चाहिए, जिनसे जानवरों की जान को खतरा न हो।

वन्यजीव विशेषज्ञ सामान्यतः सुरक्षित फेंसिंग, निगरानी और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अन्य गैर-घातक उपायों को महत्व देते हैं। इसके साथ ही बिजली से संचालित किसी भी बाड़ की नियमित जांच और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक होता है। इस घटना में संबंधित फेंसिंग सुरक्षित थी या नहीं, इसका निर्धारण जांच के बाद ही किया जा सकेगा। जांच रिपोर्ट से सामने आएगी

सच्चाई राउरकेला वन प्रभाग की टीम हाथी की मौत से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। अधिकारियों के लिए यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि हाथी की मौत कब और किन परिस्थितियों में हुई। शोक सांत्वना पाएं यदि जांच में बिजली का झटका लगने की पुष्टि होती है, तो बाड़ की तकनीकी स्थिति और बिजली आपूर्ति की जांच महत्वपूर्ण हो जाएगी। वहीं, यदि मौत का कोई अन्य कारण सामने आता है, तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। फिलहाल वन विभाग की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। वन विभाग की जांच पर टिकी निगाहें सुंदरगढ़ जिले के बिसरा ज़्लॉक स्थित डुमेरता गांव में सात वर्षीय हाथी की संदिग्ध मौत ने वन्यजीव सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हाथी खेत की सोलर फेंसिंग में फंसा मिला था, जिसके चलते करंट लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। राउरकेला वन प्रभाग की जांच और संबंधित चिकित्सकीय निष्कर्ष सामने आने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि हाथी की मौत बिजली के झटके से हुई थी या किसी अन्य वजह से।

बंगाल की खाड़ी में बड़े मौसमी बदलाव के संकेत, ओडिशा-आंध्र तट की ओर बढ़ सकता है सिस्टम

भुवनेश्वर २३/१० (संवाददाता): बंगाल की खाड़ी में एक नई मौसमी प्रणाली विकसित होने के संकेत मिले हैं, जिससे आने वाले दिनों में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मौसम बदल सकता है। मौसम संबंधी मॉडलों के अनुसार, यह प्रणाली आगे चलकर कम दबाव के क्षेत्र और उसके बाद डिप्रेशन का रूप ले सकती है। इसके दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रणाली चक्रवात में बदलेगी या नहीं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 21 अक्टूबर को थाईलैंड की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ था। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो सकता है कम दबाव का क्षेत्र मौसम विभाग के अनुसार, थाईलैंड की खाड़ी और उससे सटे थाईलैंड तथा ज़्यांमार के क्षेत्रों में एक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय था। यह प्रणाली समुद्र तल से लगभग 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई थी। इसके उजरी अंडमान सागर की ओर बढ़ने की संभावना जताई गई है। आगे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने के दौरान यह बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सकती है। मौसम विभाग के प्रारंभिक आकलन के अनुसार, 23 अक्टूबर के आसपास दक्षिण-पूर्वी और उससे सटे पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। अगले तीन दिनों में तेज हो सकती है प्रणाली आईएमडी के अनुसार, कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद मौसमी प्रणाली उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकती है।



इसके अगले तीन दिनों के दौरान और अधिक तीव्र होने की संभावना है। मौसम विज्ञान की दृष्टि से कम दबाव का क्षेत्र अधिक संगठित और शक्तिशाली होने पर डिप्रेशन का रूप ले सकता है। हालांकि, हर कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात में परिवर्तित नहीं होता। किसी प्रणाली के आगे विकसित होने की संभावना समुद्री तापमान, वायुमंडलीय हवाओं और अन्य मौसम संबंधी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसलिए फिलहाल इसके चक्रवात बनने की निश्चित घोषणा नहीं की गई है। दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश पर नजर मौसम संबंधी मॉडलों ने संकेत दिया है कि विकसित होने वाली प्रणाली दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों की दिशा में आगे बढ़ सकती है। हालांकि, यह अभी संभावित मार्ग है, अंतिम पूर्वानुमान नहीं। समुद्र के ऊपर विकसित होने वाली प्रणालियों की दिशा और तीव्रता में समय के साथ बदलाव हो सकता है। ऐसे में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मौसम विभाग के आगामी पूर्वानुमानों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल किसी विशेष जिले में चक्रवात के टकराने की पुष्टि नहीं हुई है। ज़्या चक्रवात का रूप ले सकती है प्रणाली? बंगाल की खाड़ी में मौसमी प्रणाली के विकसित होने की खबर के बाद सबसे बड़ा सवाल इसके चक्रवात बनने की संभावना को लेकर है। मौसम विभाग ने अभी केवल कम

दबाव का क्षेत्र बनने और उसके अधिक तीव्र होने की संभावना व्यक्त की है। डिप्रेशन बनने के बाद भी प्रणाली का चक्रवात में बदलना कई वायुमंडलीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि ओडिशा या आंध्र प्रदेश के तट पर चक्रवात दस्तक देगा। प्रणाली के विकसित होने के साथ मौसम विभाग उसके संभावित मार्ग और तीव्रता का अधिक सटीक आकलन कर सकेगा। तटीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना यदि मौसमी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में मजबूत होती है और तटों की ओर बढ़ती है, तो आसपास के क्षेत्रों में बादल, बारिश और हवाओं की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हालांकि, फिलहाल उपलब्ध जानकारी में किसी जिले के लिए बारिश की निश्चित मात्रा या हवा की गति का अनुमान नहीं दिया गया है। संभावित वर्षा का क्षेत्र और उसकी तीव्रता प्रणाली के वास्तविक मार्ग पर निर्भर करेगी। मौसम विभाग के अगले बुलेटिन से यह स्पष्ट हो सकेगा कि किन तटीय क्षेत्रों में मौसम का अधिक प्रभाव पड़ सकता है। मछुआरों के लिए मौसम अपडेट महत्वपूर्ण बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना समुद्र में मछली पकड़ने और अन्य गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। समुद्री मौसमी प्रणालियों के दौरान हवाओं और लहरों की स्थिति तेजी से बदल सकती है। ऐसे में मछुआरों और नाव

संचालकों को समुद्र में जाने से पहले आधिकारिक मौसम बुलेटिन देखना चाहिए। हालांकि, उपलब्ध विवरण में मछुआरों के लिए किसी विशेष तारीख से समुद्र में जाने पर प्रतिबंध या चेतावनी की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए किसी प्रतिबंध को लागू मानने के बजाय मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की आधिकारिक सलाह का पालन करना आवश्यक है। मौसम विभाग के अगले बुलेटिन पर नजर मौसम विभाग के प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार, 23 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है। इसके बाद अगले तीन दिनों में प्रणाली की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। आगामी मौसम बुलेटिन से इसके मार्ग, संभावित प्रभाव और तीव्रता के बारे में अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है। तटीय क्षेत्रों के लोगों को अफवाहों से बचने और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की सलाह दी जाती है।

संबलपुर २३/१० (संवाददाता): पूर्व तट रेलवे के संबलपुर मंडल ने विशेष अभियान 6.0 के तहत 22 अक्टूबर, 2026 को मंडल के सभी स्टेशनों पर रेल जन संवाद (यात्री संपर्क कार्यक्रम) का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य रेल उपयोगकर्ताओं के साथ सीधे संवाद के माध्यम से यात्रियों की भागीदारी को मजबूत करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और रेल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना था। कार्यक्रम के दौरान, यात्रियों को स्टेशन की सुविधाओं, रेलवे परिसर और ट्रेनों की साफ-सफाई, सुरक्षा उपायों और समग्र सेवा वितरण के संबंध में अपने अनुभव, सुझाव और प्रतिक्रिया (फीडबैक) साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस पहल ने यात्रियों को रेलवे अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत करने और उन क्षेत्रों को उजागर करने का एक मंच प्रदान किया, जिन पर ध्यान देने और सुधार करने की आवश्यकता है। संबलपुर रेलवे स्टेशन पर, संबलपुर के मंडल



रेल प्रबंधक, श्री सुबाष सी.चौधरी ने यात्रियों और रेल उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। उन्होंने स्टेशन की साफ-सफाई, एस्केलेटर (स्वचालित सीढ़ी) सुविधाओं, ट्रेनों में खान-पान (कैटरिंग) सेवाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं जैसी विभिन्न यात्री सुविधाओं पर फीडबैक लिया। श्री चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि कमियों की पहचान करने और रेल सेवाओं को बेहतर बनाने में यात्रियों का फीडबैक महत्वपूर्ण भूमिका

निभाता है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान प्राप्त सुझावों से मंडल को यात्री सुविधाओं को बढ़ाने, सेवा मानकों में सुधार करने और यात्रा के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए उचित कदम उठाने में मदद मिलेगी। यात्रियों की ओर से इस कार्यक्रम को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली।

उन्होंने अपने विचार साझा करने और रेलवे अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत करने के इस अवसर की सराहना की। इस तरह की

पहल रेलवे और उसके उपयोगकर्ताओं के बीच संवाद को मजबूत करती है, और सेवा वितरण में एक जवाबदेह, पारदर्शी तथा यात्री-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। विशेष अभियान 6.0% के अंतर्गत %रेल जन संवाद% के माध्यम से, संबलपुर मंडल साफ-सफाई, यात्री सुविधाओं और समग्र रेल सेवाओं में निरंतर सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है, जिसमें यात्रियों की संतुष्टि और जन भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है।

आरएसपी के पीबीएस में ऊर्जा क्वालिटी सर्किल 'ऊर्जा' ने विशिष्ट भाप खपत को अनुकूलित किया

राउरकेला २३/१० (संवाददाता): सेल के राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) के इंस्ट्रुमेंटेशन एवं ऑटोमेशन विभाग, सीपीपी-१ (पावर एंड ज़्लोइंग स्टेशन) की क्वालिटी सर्किल 'ऊर्जा' ने स्टीम टर्बाइन जनरेटर एसटीजी-1 और एसटीजी-2 में विशिष्ट भाप खपत को अनुकूलित करने की परियोजना सफलतापूर्वक लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य अत्यधिक विशिष्ट भाप खपत की समस्या का समाधान करना, टर्बाइन की दक्षता में सुधार करना तथा विद्युत उत्पादन की लागत को कम करना था। क्वालिटी सर्किल पद्धति का उपयोग करते हुए टीम ने कम



कंडेनसर वैक्यूम, इजेक्टर प्रणाली की कार्यक्षमता में गिरावट, ग्लैंड स्टीम सीलिंग में अक्षमता तथा भाप के रिसाव जैसे प्रमुख कारणों की पहचान की। व्यवस्थित मूल कारण विश्लेषण के आधार पर

सुधारात्मक उपाय विकसित किए गए और उन्हें लागू किया गया। इन पहलों के परिणामस्वरूप, 16 मेगावाट विद्युत उत्पादन के दौरान भाप की खपत 73.60 टन प्रति घंटा से घटकर 71.36

टन प्रति घंटा रह गई। इस प्रकार, प्रति घंटे 2.24 टन भाप की बचत हासिल की गई। सुधार के बाद विशिष्ट भाप खपत 4.46 किलोग्राम प्रति किलोवाट-घंटा दर्ज की गई, जबकि निर्धारित

लक्ष्य 4.40 किलोग्राम प्रति किलोवाट-घंटा था। यह परियोजना दर्शाती है कि टीमवर्क, व्यवस्थित समस्या-समाधान और निरंतर निगरानी के माध्यम से आरएसपी में ऊर्जा संरक्षण, लागत में कमी तथा परिचालन दक्षता में सुधार के लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। क्वालिटी सर्किल 'ऊर्जा' की टीम में श्री कृष्ण नायक और श्री ए. के. बेहरा, दोनों इंजीनियरिंग एसेसिएट्स, तथा श्री बी. साहू और श्री आर. साहू, दोनों जूनियर इंजीनियरिंग एसेसिएट्स शामिल हैं। टीम के फैसिलिटेटर वरिष्ठ प्रबंधक (पीबीएस) श्री संतोष कुमार हैं।